(d) whether the Government proposes to change this system of collecting data and if not, why?

Instead of making, a speech I have only divided my question into four parts.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: We have a standard and by that standard, we see whether a particular village is electrified. After all, the Rural Electrification Corportion is not a charitable institution. They also look into the demands, underground water resources. All these factors are taken into consideration. I do not have any information at my disposal to inform the hon. Member that the Rural Electrification people have given wrong information.

श्री छोतभाई गामित : गुजरात में आदिवासियों के कई गांवों में इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है लेकिन गांव में जहां आदिवासियों और हरजिनों की बस्तियां है वहां कई सालों से बिजली की लाइन नही दी गई है। जहां तहां इस तरह से जो इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है वहां आदिवासियों और हरजिनों की बस्तियां जो बाकी रह गई है उन बस्तियों को लाइन देने की कोई योजना आपने बनाई है और बनाई है तो कब तक उनको बिजली द दी जाएगी ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: We will give the top most priority to Harijan bastis and tribal areas.

SHRI K. A. RAJAN: Does cent per cent electrification of a village mean drawing a line or giving lights to all the consumers of that village?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: As I have said already, I do not have such information. I will pass on this information. But there is another issue to be looked into. It is, if a particular village is electrified, assuming that the contention of the hon. Member is. . .

MR. SPEAKER: That is too far fetched now.

Question No. 112.

छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन दिया जाना

***112. श्री राम लाल राही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन दिये जाने की नीति के विरुद्ध कुछ समाचार पत्रों को विज्ञापन दिये जाते हैं जिसके कारण असंतोष फैलता है, और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे है ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b). No, Sir. No advertisements are given against policy. However with a view to remove the imbalance Government is considering the review of the advertisement policy so that small and medium newspapers get more encouragement.

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने असंतुलन को स्वीकार किया है, इसके माने असमानता है विज्ञापन देने में । तो इस असंतुलन को दूर करने के लिये वह जल्दी से क्या कदम उठा रहे हैं ? तथा छोटे समाचार पत्रों को प्रोत्साहन देने के लिये उनके पास क्या कोई ठोस योजना है ? यदि हां, तो उस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री वसन्त साठे : यही तो मैंने कहा कि कि इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और हम एक कमेटी बैठा रहे हैं अपने मंत्रालय के अन्तर्गत यह देखने के लिये। जो कुछ असंतुलन होगा और उसे ठीक करने के लिये जो उपाय हम अमल में लायेंगे, जैसे ही हमारी योजना इस बारे में तैयार हो जायगी, उस में आपको विदित करा दूंगा।

श्री राम लाल राही : मंत्री जी को याद होगा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले समय में छोटे समाचार पत्रों में काम करने वाले सम्पादकों को और दूसरे लोगों को जो समाचार एकत्र करते थे उन्हें रेल सुविधा के फ्री पास जारी करने का प्रस्ताव किया था । क्या मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे और इन लोगों को रेल सुविधा फ्री देने की बात निश्चित करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : यह बात तो रेल मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके ही तय की जा सकती है । हम खुद तो रेल पास दे नहीं सकते। पर जो सुझाव माननीय मित्र ने दिया है हम जरूर रेलवे मंत्रालय से इसके बारे में विचार-विमर्श करेंगे।

SHRI CHARANJI LAL SHARMA: Will the hon. Minister be pleased to state the criteria for giving advertisements to the small newspapers and magazines?

SHRI VASANT SATHE: There are no specific criteria laid down. But the general advertisement policy is based on the circulation of the newspapers and magazines and, on that basis, there are certain criteria and advertisements are given accordingly. But I realise—I can take the House into confidence—that there is a certain imbalance. The bigger news papers do take away a large chunk of advertisements and smaller ones don't. That is why, as I said in the beginning, I am having a fresh look at it. Unless the whole thing is formulated, I cannot come out with specific proposals. But I will do it as early as I can.

श्री चन्द्रपाल शैलानी: क्या मंत्री जी की जानकारी में यह है कि पिछले 20, 25 साल से जो अखबार नियमित रूप से निकल रहे हैं उनको आज तक डी०ए०वी०पी० तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं, जब कि इसके विपरीत जिस अखबार का जन्म भी नहीं होता उसको डी०ए०वी०पी० के विज्ञापन दे दिये जाते हैं? अगर यह सही है तो ऐसा पक्षपात क्यों है? मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि देश में तहसील और जिला स्तर पर छोटे छोटे समाचार-पत्र निकलते हैं और वह समाचार छापते हैं जिनको बड़े अखबार नहीं छापते । जो स्थानीय समस्यायें होती हैं उनकी ओर सरकार और जिलाधिकारियों का ध्यान दिलाते हैं, लेकिन धनाभाव के कारण, विज्ञापन न मिलने के कारण वह अखबार टूट जाते हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो तहसील और जिला स्तर पर समाचार-पत्र निकलते हैं उनको विज्ञापन देने में तथा अन्य आर्थिक सुविधायें देने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और किस-किस तरह की मदद देने का सरकार का विचार है?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस तरह के वाकयात हुए हैं कि जिला स्तर पर जो छोटे अखबार निकलते हैं उनको सुविधायें प्राप्त नहीं होती रही हैं, और इसीलिये मैंने कहा कि यह सारे प्रश्न और जो हमारी नीति है छोटे जिला स्तर के अखबारों को मदद करने की उस नीति को ध्यान में रखते हुए हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं । और यदि कोई खास केस माननीय सदस्य की नजर में हो जहां 20 साल से अखबार निकल रहा है और उसको मदद नहीं मिली है तो कृपया उसको आप मेरे ध्यान में लाइये, मैं उसको मदद दिलाने की कोशिश करूंगा।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Deaths due to starvation in the Refugees Camp, Raigarh (M.P.)

*104 SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the death of four persons in the Bengali Refugees' Camp near Dharmajaigarh in Raigarh District of Madhya Pradesh due to starvation;

(b) if so, what steps have been taken by Government to give foodgrains and doles to the suffering refugees; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI VASANT SATHE): (a) No "camp" of migrants from former East Pakistan is presently located at or near Dharamjaigarh. Some families of erstwhile migrants have, however, been settled on agriculture in villages in and around Dharamjaigarh.

The Government of Madhya Pradesh have reported that there have been no deaths due to starvation.

(b) and (c). Do not arise. However, relief work have been taken up in the drought-affected areas.